

प्रेषक,

मनीषा पंवार,

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड,

भोपालपानी, देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 30 सितम्बर, 2016

विषय:—वित्तीय वर्ष, 2016-17 में श्री गांधी जयन्ती (02 अक्टूबर) के शुभ अवसर पर खादी वस्त्रों की बिक्री पर 108 कार्यकारी दिवसों हेतु 10 प्रतिशत छूट की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या:—998/VII-2-16/111-एम0एस0एम0ई0/2015 दिनांक 26.05.2016 द्वारा प्रदेश में खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना के स्थान पर दिनांक 01.04.2016 से "विपणन विकास सहायता योजना" (एम0डी0ए0) लागू की गयी है।

2. शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.04.2016 से "विपणन विकास सहायता योजना" (एम0डी0ए0) योजना लागू किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या:—998/VII-2-16/111-एम0एस0एम0ई0/2015 दिनांक 26.05.2016 को निरस्त करते हुए पुनः "खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट" योजना संचालित करने तथा विगत वर्षों की भांति ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में खादी वस्त्रों के प्रोत्साहन हेतु राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में उत्पादन तथा बिक्री से सम्बद्ध पंजीकृत संस्थाओं को खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत छूट दिनांक 02 अक्टूबर, 2016 से 108 कार्यकारी दिवसों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. संस्था को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड द्वारा निर्गत पंजीकृत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।
2. संस्थाओं द्वारा रिबेट दावों के साथ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्वीकृत उत्पादन/बिक्री का वार्षिक लक्ष्यांक का प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. रिबेट दावों के साथ संगत अवधि का बैंक स्टेटमेन्ट संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
4. इंगित अवधि का प्रारम्भ से अंत तक कच्चे माल तथा उत्पादित माल की स्टॉक सूची का विवरण संलग्न किया जाना होगा।
5. इंगित अवधि में संस्था द्वारा व्यय एवं स्रोत का विवरण तिथिवार संगत साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करना होगा।
6. रिबेट दावों परीक्षण मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर पर किया जाएगा।

7. संस्थाओं के रिवेट दावों के सापेक्ष उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत उत्पादित सामान की आपूर्ति किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2926/VII-II-08/2004-उद्योग/01 दिनांक 03.11.2008 के निर्देश यथावत लागू माने जायेंगे।
8. संस्था को बैंक/खादी और ग्रामोद्योग आयोग से वित्त पोषित होने का साक्ष्य भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. संस्थाओं को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के०बी०आई०सी०) से विपणन विकास सहायता (एन०डी०ए०) में जितनी सहायता प्राप्त हुई है, उसी आधार पर उत्पादन की मात्रा का सत्यापन किया जायेगा।
3. उक्त छूट हेतु राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं राज्य सरकार/उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(मनीषा पंवार)


प्रमुख सचिव।

संख्या: 1634(1)/VII-2-16/204-उद्योग/2001, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महल्लेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इरला रोड विले पारले, पश्चिमी मुम्बई-56
10. निदेशक, राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव।